>

Title: Need to ensure accessibility of the benefits of multipurpose irrigation projects like Bansagar in Rewa, Madhya Pradesh.

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): माननीय सभापति जी, किसान हित में अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र रीवा, मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार एवं तीनों राज्य - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सहयोग से बन रही बाणसागर बहुद्देश्यीय जीवनदायिनी बृहद परियोजना की पूर्व नहर की नौवस्ता वितरक नहर से निकलने वाली सुमेदा और अतरौली माइनर नहरों से जेपी एसोसियेट्स के आवेदन पर क्रमशः सुमेदा का 749 हैक्टेयर तथा अतरौली का 51 हैक्टेयर, दोनों गाँवों का कुल रकबा 800 हैक्टेयर यानी 2000 एकड़ कृषि भूमि को माइनिंग लीज़ क्षेत्र दर्शाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई गाँवों को सिंचाई से वंचित किया जा रहा है जबकि विभाग द्वारा उचित सर्वेक्षण पश्चात् नहर का एलाइनमैंट निर्धारित कर नहर हेतु भू-अर्जन का कार्य पूर्ण कर निविदा आमंत्रित कर नहर की खुदाई भी करा दी गई है। जेपी एसोसियेट्स के द्वारा षडयंत्रपूर्वक जल संसाधन विभाग को आवेदन देकर अपने प्रभाव एवं पैसे का उपयोग कर लीज़ क्षेत्र में फँस रही लगभग 200 मीटर लंबी कैनाल को मुद्दा बनाकर दोनों गाँवों के पूरे रकबे को लीज़ क्षेत्र बताकर बाणसागर के अधिकारियों को अपने दबाव में लेकर झूठा प्रतिवेदन दिलाकर नौवस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी का सात किलोमीटर नहर का एलाइनमैंट बदलवा दिया।

जबकि जेपी सीमेंट की मात्र दो सौ मीटर लंबी जमीन ही नहर क्षेत्र से प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से सिर्फ उद्योगपति को एकतरफा लाभ पहुंचाने की नीयत से किसानों को भविष्य में होने वाले लाभ और देश में होने वाले कृषि उत्पादन को ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि परिवर्तित एलाइनमेंट का नक्शा जेपी सीमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित रुकी हुई स्वीकृत नहर के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.